वर्ष 1 · अंक **13**
जयपुर, बुधवार, 11 नवंबर 2026
सप्ताह 2 – 11 नवंबर 2026

The Consulting Crew
GST · इनकम टैक्स · ROC · पेरोल · सलाह
क्लाइंट्स और दोस्तों के लिए मुफ़्त

THE CONSULTING CREW

आज के समाचार

BUSINESS WEEKLY

हर खबर जो आपके बिज़नेस के काम आए

ब्रेंट	10 साल की G-sec	निफ्टी 50	FII (हफ़्ता)	रुपया	अगली तारीख़
$91.33	~7.15%	25,030.35	+₹45,960 cr	94.47/$	21 Nov
▼ 23 अक्तूबर के $116.72 से	▼ तीन हफ़्ते पहले 7.474%	▲ 6 नवंबर तक के हफ़्ते में +8.58%	▲ हफ़्तों की बिकवाली के बाद ख़रीदार	▲ 21 अक्तूबर के बाद सबसे अच्छा	ITR, ऑडिट वाले

इस अंक में 1 कच्चा तेल 2 टैक्स 3 GST 4 कर्ज़ 5 लागत 6 व्यापार 7 राजस्थान 8 संदर्भ + ज़रूरी तारीख़ें

हफ़्ते की पाँच बड़ी बातें

नुक़सान के हिसाब से क्रम · हर लाइन अपना डेस्क खोलती है

1 ब्रेंट दो हफ़्ते में करीब पाँचवाँ हिस्सा गिरकर **$91.33** — और वह भी एक ऐसे draft पर जिस पर दस्तख़त नहीं हुए। दाम न घटाएँ, न बढ़ाएँ।
कच्चा तेल

2 ऑडिट केस का रिटर्न **21 नवंबर** को due है। सेक्शन 234A 31 अक्तूबर से 1% महीना ब्याज ले रहा है।
टैक्स

3 GST रिटर्न में **दस दिन**, और उस महीने में उन्नीस जो तय करेगा कि ब्याज आख़िर में कितना पड़ेगा।
संदर्भ

4 सीधे allotment की जो window इस अख़बार ने बंद बताई थी, वह बढ़ गई। अब **20 नवंबर** को बंद होगी।
राजस्थान

5 US Treasury ने vessel certification पर भारतीय फ़र्मों पर sanction लगाए हैं, और आप पर कौन सा tariff लगेगा यह अभी तय नहीं है।
व्यापार

बड़ी खबर · कच्चा तेल

बैरल से जंग का प्रीमियम निकल गया, और उसके साथ पूरी दलील भी

पिछले अंक के बाद से ब्रेंट क़रीब पाँचवाँ हिस्सा गिर चुका है। महँगे पैसे और महँगे inputs की पाँच अंकों की चेतावनी एक पखवाड़े में उलट गई। यह अंक बुधवार का है क्योंकि देर से आया है, और रविवार की तारीख़ डालना झूठ होता।

23 अक्तूबर को $116.72 · 30 को ~$113 · 10 नवंबर को $91.33

दस्तख़त कुछ पर नहीं हुए, और फिर भी भाव हिल गया। नवंबर की शुरुआत में अमेरिका–ईरान जंग ख़त्म करने का एक मसौदा चलने लगा, जब ईरानी वार्ताकार क़तर से निकले। उसकी शर्तें सामने नहीं आईं। किसी युद्धविराम पर दस्तख़त नहीं हुए। होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों पर ईरानी हमले गिरावट के दौरान भी चलते रहे और **11 नवंबर** को फिर हुए। और सिर्फ़ उस मसौदे के दम पर ब्रेंट 23 अक्तूबर के **$116.72** से 30 को क़रीब **$113**, 3 नवंबर को **$103.60** — 7 अक्तूबर के बाद का सबसे नीचा बंद भाव — और **10 नवंबर** को **$91.33** पर आ गया, अगस्त के बाद सबसे नीचे, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जंग "असल में ख़त्म" है।

जिस-जिस के लिए यह अख़बार आपको तैयार कर रहा था, वह सब उसी पखवाड़े में उल्टा चला। 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड, जिस पर अंक 11 की बड़ी ख़बर **7.474%** पर बनी थी और जिसे बिना ऐलान पैसे का महँगा होना कहा गया था, वापस क़रीब **7.15%** पर है — पूरी बढ़त लौट गई। रुपया मज़बूत होकर **94.47** पर आया, 21 अक्तूबर के बाद सबसे अच्छा। जो विदेशी संस्थाएँ हफ़्तों से बेच रही थीं, उन्होंने 6 नवंबर तक के हफ़्ते में शुद्ध **₹45,960 करोड़** के भारतीय शेयर ख़रीदे, और निफ्टी **8.58%** चढ़कर **25,030.35** पर पहुँचा — लगातार सात सत्र, चौदह महीने की सबसे लंबी दौड़। सस्ते कच्चे तेल को अब इस गुंजाइश की तरह भी पढ़ा जा रहा है कि RBI **2–4 दिसंबर** को बस रुका रहे।

अब जो लालच है वह ठीक उस ग़लती का आईना है जिसके ख़िलाफ़ यह अख़बार पूरा अक्तूबर चेताता रहा — और उतना ही महँगा है। अक्तूबर में ग़लती यह थी कि नवंबर का काम सितम्बर की लागत पर quote किया जाए। नवंबर में ग़लती यह है कि दाम उस बैरल के हिसाब से घटा दिए जाएँ जो इसलिए सस्ता है कि एक काग़ज़ चल रहा है जिस पर न किसी ने दस्तख़त किए हैं, न जिसे किसी ने पढ़ा है। ब्रेंट अब भी साल भर पहले से **40.7% ऊपर** है। 11 नवंबर को हमले फिर हुए तो वह फिर चढ़ा। जो भाव एक मसौदे पर बीस प्रतिशत हिल सकता है वह बातचीत टूटने पर बीस प्रतिशत वापस भी हिल सकता है — और दोनों दिशाओं में आपको बचाने वाली चीज़ एक ही है।

> जो दाम एक draft पर बीस फ़ीसदी हिला, वह
> बातचीत टूटने पर बीस फ़ीसदी वापस भी जा सकता है।
>
> **इसी पन्ने की दलील से**

आपको क्या करना है

न दाम घटाइए, न बढ़ाइए। वही **ईंधन clause** इस्तेमाल कीजिए जिस पर यह अख़बार तीन अंक से ज़ोर दे रहा है: दाम quotation की तारीख़ की ईंधन लागत मानकर है और तय दायरे से बाहर किसी भी तरफ़ हिलने पर फिर खुलेगा। पखवाड़ा भर पहले उसी clause ने आपको $116 वाले बैरल से बचाया। आज वह आपको इस वादे से बचा रहा है कि मार्च की डिलीवरी $91 वाले दाम पर देंगे। इस हफ़्ते करने लायक़ एक ठोस काम दाम बदलने का उल्टा है: अगर आपके पास अक्तूबर के स्तर पर लिया forward cover या तय दाम वाला supply contract है, तो उसका mark-to-market अभी लिखवा लीजिए, जब तक आँकड़ा जाना जा सकता है — renewal पर पता चलने से पहले।

ज़रूरी तारीख़ें

नवंबर – दिसंबर 2026

11 नव — आज ही
GSTR-1
अक्तूबर, मासिक भरने वाले — आज

12 नव — कल
अक्तूबर का CPI
deadline नहीं। तब नापा गया जब ब्रेंट $113 था — बाज़ार से पहले ही पीछे

15 नव — 4 दिन बाकी
TDS certificates — Q2
deductees को Form 16A

16 नव — 5 दिन बाकी
अक्तूबर का WPI
deadline नहीं। उसी बासी सवाल का थोक वाला हिस्सा

20 नव — 9 दिन बाकी
GSTR-3B · RIICO बंद
अक्तूबर, मासिक भरने वाले — और जोधपुर-पाली-मारवाड़ के आवेदन का आख़िरी दिन

21 नव — 10 दिन बाकी
ITR — ऑडिट वाले
234A return देने तक चलता है, टैक्स चुकाने तक नहीं

30 नव — 19 दिन बाकी
ITR — transfer pricing
s.92E वाले मामले। सस्ते ब्याज वाले महीने का आख़िरी दिन भी

4 दिस — 23 दिन बाकी
MPC का फ़ैसला
बैठक 2–4 दिसंबर। सस्ता कच्चा तेल अब रुकने की गुंजाइश माना जा रहा है

7 दिस — 26 दिन बाकी
TDS जमा
नवंबर का

11 दिस — 30 दिन बाकी
GSTR-1
नवंबर, मासिक भरने वाले

15 दिस — 34 दिन बाकी
Advance tax — Q3
तीसरी क़िस्त, कुल का 75%

टैक्स · दस दिन

ऑडिट वालों की return 21 को देय है, और 234A अभी से चल रहा है

ऑडिट वालों की ITR · 21 नवंबर · s.234A तब तक, जब तक वह दी न जाए

दस दिन, और और पैसे वाली घड़ी पखवाड़ा भर पहले चल पड़ी थी। ऑडिट वालों की return **21 नवंबर** को देय है। जिन्होंने **31 अक्तूबर** तक self-assessment tax नहीं भरा — वही तारीख़ जिस पर इस अख़बार ने तीन अलग ज़िम्मेदारियाँ रखी थीं — उन पर तब से **section 234A** 1% महीना लगा रहा है, और वह तब तक चलता है जब तक return *दी* न जाए, टैक्स चुकाने तक नहीं। **234B** advance tax की कमी पर अलग से लग रहा है। दोनों में **महीने का कोई भी हिस्सा पूरा महीना** गिना जाता है — और यही नियम तय करता है कि यह कितने का पड़ेगा।

इससे इस महीने का हिसाब असामान्य रूप से आसान हो जाता है — और 21 को नहीं, उससे पहले कर लेना चाहिए। **30 नवंबर** तक की filing और 1 दिसंबर की filing दोनों धाराओं पर पूरे एक महीने के ब्याज से अलग हैं — ₹10 लाख बक़ाया टैक्स पर एक दिन के लिए क़रीब **₹20,000**। देय तारीख़ 21 है, इसलिए 30 के पास जाने की कोई वजह नहीं; बात यह है कि अगर कुछ 21 से आगे खिसके, तो वह महीने से आगे न खिसके। और **section 92E** वाला रास्ता अलग है और बाद का: वह return **30 नवंबर** को देय है।

एक चीज़ नहीं हिली है और उसे साफ़ कहना बनता है, क्योंकि उल्टा मान लिया जा रहा है। कोई और extension नहीं आया। CBDT ने सितम्बर में **Circular 07/2026** से ऑडिट रिपोर्ट 21 अक्तूबर और return 21 नवंबर की थी, और उसके बाद कुछ अधिसूचित नहीं किया। इस अख़बार ने अंक 10 में कहा था कि तीसरी तारीख़ नहीं आएगी; नहीं आई, और दस दिन बचे होने पर उसका कोई संकेत भी नहीं है। 21 के हिसाब से ही योजना बनाइए।

> **आपको क्या करना है**
>
> आज अपने accountant से एक आँकड़ा माँगिए: 234A और 234B का ब्याज *आज की तारीख़ में*, रुपयों में। उन्हें दस मिनट लगेंगे और अस्पष्ट चिंता फ़ैसले में बदल जाएगी — वह रक़म आम तौर पर या तो इतनी छोटी निकलती है कि सोचना छोड़ दें, या इतनी बड़ी कि इसी हफ़्ते निपटा दें। फिर **21** तक भर दीजिए, और अगर कुछ खिसकना ही है तो वह नवंबर के भीतर खिसके, बाहर नहीं। समूह में कहीं भी section 92E लागू है तो वह return **30 नवंबर** का अलग काम है और अलग accountant का; उसे 21 के बाद नहीं, अभी शुरू कीजिए।

20 दिस — 39 दिन बाकी

GSTR-3B
नवंबर, मासिक भरने वाले

31 दिस — 50 दिन बाकी

देर से या संशोधित ITR
AY 2026-27, जहाँ लागू हो

ये आम तारीख़ें हैं। सरकार आगे बढ़ाए तो अगले अंक में बता देंगे। टर्नओवर और राज्य के हिसाब से फ़र्क़ पड़ता है — भरोसा करने से पहले एक बार पूछ लीजिए।

सारी तारीख़ें कैलेंडर में डालें

TCC की सलाह

इस हफ़्ते ये तीन काम कर लीजिए

1. **बैरल देखकर दाम मत बदलिए — किसी भी तरफ़।** ब्रेंट बिना दस्तख़त वाले मसौदे पर पाँचवाँ हिस्सा गिरा है और साल भर में अब भी 40.7% ऊपर है। **ईंधन clause** इस्तेमाल कीजिए: दाम quotation की तारीख़ की ईंधन लागत मानकर, और तय दायरे से बाहर दोनों तरफ़ फिर खुलेगा।

2. **इस हफ़्ते 234A और 234B का आँकड़ा रुपयों में ले लीजिए।** ऑडिट वालों की ITR **21 नवंबर** को देय है और ब्याज अभी से चल रहा है। महीने का हिस्सा पूरा महीना गिना जाता है, इसलिए पक्का कीजिए कि कुछ **30 नवंबर** से आगे न खिसके।

3. **जोधपुर-पाली-मारवाड़ अब भी खुला है — हमने बंद बताया था।** RIICO ने उसे **20 नवंबर** तक बढ़ाया: 30 भूखंड, 28 औद्योगिक। उसी फ़ोन में क्षेत्रीय कार्यालय से पूछिए कि 1 सितम्बर के आदेश की **दस साल की क़िस्त** सुविधा के लिए आपका क्षेत्र पात्र है या नहीं।

GST · चौंतीस दिन बाद

अब भी कोई अधिसूचना नहीं — और एक पाठ सुधारों को अप्रैल 2027 पर ले जाता है

57वीं काउंसिल 8 अक्तूबर · s.69 के लिए संसद · s.17(5) के लिए संशोधन

यह लगातार चौथा अंक है, और और जवाब नहीं बदला। 57वीं काउंसिल की बैठक के चौंतीस दिन बाद उसकी एक भी सिफ़ारिश अधिसूचित नहीं हुई है। इस बीच जो आया वह 9 अक्तूबर के **FAQ** हैं और ढेर सारी टिप्पणी। जो नहीं आया वह क़ानून में बदलाव है। दोनों बड़ी बातों के लिए अधिसूचना से ज़्यादा चाहिए: गिरफ़्तारी का अधिकार हटाने का मतलब CGST Act की **section 69** हटाना है, जिसके लिए संसद और राज्य विधानसभाओं को Act में संशोधन करना होगा; credit चौड़ा करने का मतलब **section 17(5)** में संशोधन, जो वही समस्या है।

टिप्पणियों में अब एक तारीख़ घुस आई है जिसे पाठक दोनों तरफ़ से सावधानी से लें। कम से कम एक विश्लेषण बदलावों को **1 अप्रैल 2027** से लागू बताता है; दूसरा सिर्फ़ इतना कहता है कि पहले संसद को संशोधन पारित करना होगा, तारीख़ बताए बिना। यह अख़बार इसे हल नहीं करेगा — उसी वजह से जिससे उसने tariff की दर हल नहीं की: स्रोत आपस में नहीं मिलते और उनमें से कोई सरकार नहीं है। कहा यह जा सकता है कि **अप्रैल 2027** का आँकड़ा अब एक से ज़्यादा तरफ़ से चल रहा है — ITC mismatch वाली व्यवस्था हमेशा उसी return अवधि से प्रस्तावित थी — और यह कि उसके किसी भी पाठ से उस return को मदद नहीं मिलती जो आप इस महीने भर रहे हैं।

इसलिए कारोबार के लिए व्यावहारिक स्थिति चौथे अंक में भी वही है — और यही बता देना सेवा है। गिरफ़्तारी, मुक़दमा, जुर्माना और pre-deposit के प्रावधान ठीक वैसे ही लागू हैं जैसे सितम्बर में थे। मुक़दमे की लागू सीमा ₹1 करोड़ है, ₹5 करोड़ नहीं। कर्मचारियों के health और life insurance पर credit रुका हुआ है। 8 अक्तूबर के बाद किसी सुर्ख़ी के भरोसे जिसने उल्टा किया है, उसे पलटना है — और ख़ुद से पलटने की क़ीमत, पूछे जाने पर पलटने से कहीं कम है।

कर्ज़ · पूरा चक्कर

तीन हफ़्ते पहले जिन 28 आधार अंकों पर बड़ी ख़बर बनी थी, वे वापस जा चुके हैं

10 साल की यील्ड 23 अक्तूबर को 7.474% · 10 नवंबर को क़रीब 7.15%

अंक 11 की बड़ी ख़बर यही थी, और और दूसरा आधा बताना भी बनता है। उस अंक ने कहा था कि MPC ने रेपो 25 आधार अंक बढ़ाया, जबकि बॉन्ड बाज़ार ने चुपचाप 28 और जोड़ दिए — और **MCLR** वाला कर्ज़दार दोनों ले रहा है जबकि **EBLR** वाला सिर्फ़ पहला। तब से 10 साल की यील्ड 7.474% से लौटकर क़रीब **7.15%** पर है, और रुपया **94.47** पर। यह कच्चे तेल ने किया: जिस मसौदे ने बैरल से पाँचवाँ हिस्सा निकाला, उसी ने यील्ड से महँगाई का प्रीमियम निकाल दिया। स्रोत मौजूदा स्तर श्रृंखला के हिसाब से क़रीब 7.12% से 7.20% के बीच बताते हैं — यह आम फ़ासला है, असहमति नहीं।

कर्ज़दार के लिए इसका मतलब उसी benchmark पर टिका है जिस पर पिछला लेख टिका था — और दोनों के लिए जवाब सचमुच अलग है। आपका कर्ज़ **EBLR** पर है तो कुछ नहीं हुआ: वह रेपो से जुड़ा है, रेपो अब भी **5.50%** है, और MPC के हिलने तक वहीं रहेगा। आपका कर्ज़ **MCLR** पर है तो बैंक की लागत नरम हुई है और आपके अगले reset में वह दिखना चाहिए — मगर वह ख़ुद ऐलान नहीं करेगा, जैसे बढ़ोतरी ने नहीं किया था। MCLR की गिरावट आप तक सिर्फ़ आपकी reset तारीख़ पर पहुँचती है, और तभी जब बैंक उसे आगे बढ़ाए — जो बैंक नीचे की तरफ़ भरोसेमंद ढंग से धीरे करते हैं।

नतीजतन दिसंबर की नीति की शक्ल बदल गई है। महीना भर पहले कुछ अर्थशास्त्री **2–4 दिसंबर** की MPC में बड़े क़दम की बात कर रहे थे; कच्चा तेल क़रीब पाँचवाँ हिस्सा गिरने के बाद अब पाठ यह है कि सस्ता तेल बैंक को रुकने की गुंजाइश देता है। इनमें से कोई भी पाठ कभी ऐसा अनुमान नहीं था जिस पर अमल हो सके, और यह अख़बार कोई अनुमान लगा भी नहीं रहा। अमल लायक़ बात छोटी है: दिसंबर में रुकना और MCLR का नरम होना, दोनों अगली तिमाही में reset वाले किसी के लिए एक ही तरफ़ इशारा करते हैं — और यह बात तारीख़ के बाद नहीं, पहले करनी चाहिए।

आपको क्या करना है

इस महीने की filing में कुछ नहीं बदलता — लगातार चौथे अंक में। 8 अक्तूबर के बाद किसी ने **कर्मचारियों के बीमा** पर credit खोला हो तो इसी हफ़्ते अपने हाथ से पलट दीजिए। फिर सारांश पढ़ना बंद कीजिए: हर महीने के पहले कामकाजी दिन का reminder लगाइए कि **CBIC का notifications पन्ना ख़ुद** खोलें। सिफ़ारिश उसी दिन क़ानून बनती है जिस दिन अधिसूचना कहती है, उससे एक घंटा पहले नहीं — और यहाँ तो पहले संसद का अधिनियम चाहिए, इसलिए देखने की चीज़ शीतकालीन सत्र है, टिप्पणी नहीं।

आपको क्या करना है

sanction letter फिर निकालिए और वही दो चीज़ें देखिए: **EBLR या MCLR**, और **reset की तारीख़**। MCLR लिखा है और reset अगली तिमाही में है, तो बैंक को अभी लिखकर उस reset पर नई दर और नई अवधि पूछिए — वही सवाल जो इस अख़बार ने तीन हफ़्ते पहले रखा था, और जिसका जवाब अब कम भी आ सकता है। बैंक गिरावट धीरे आगे बढ़ाते हैं और ख़ुद से लगभग कभी नहीं बताते, इसलिए माँग आपकी तरफ़ से आनी होगी। EBLR लिखा है तो कुछ नहीं बदला और MPC के हिलने तक आपका कुछ बकाया नहीं है।

व्यापार · प्रतिबंध

अमेरिकी ट्रेज़री ने जहाज़ों के प्रमाणन पर भारतीय फ़र्मों पर प्रतिबंध लगाए

ईरानी पेट्रोलियम ढोने वाले जहाज़ों के झूठे प्रमाणन · भारतीय और तुर्की फ़र्में

गिरता तेल अच्छी ख़बर है, और और यही उसका वह हिस्सा है जो अच्छी ख़बर नहीं है। **अमेरिकी ट्रेज़री** ने ईरानी पेट्रोलियम ढोने वाले जहाज़ों के कथित झूठे प्रमाणन पर **भारतीय और तुर्की फ़र्मों** पर प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ नाम और ब्योरा उतना मायने नहीं रखता जितनी श्रेणी: ये तेल ख़रीदने पर प्रतिबंधित तेल कंपनियाँ नहीं हैं। ये काग़ज़ी शृंखला की फ़र्में हैं — प्रमाणन, निरीक्षण, दस्तावेज़ीकरण — जिन पर इसलिए प्रतिबंध लगा कि काग़ज़ों में क्या लिखा था। यह अलग ख़तरा है, और वह दूसरी तरह के कारोबारों तक पहुँचता है।

जयपुर के निर्यातक के लिए इसका मतलब ईरानी तेल नहीं है। मतलब यह है कि माल के बारे में भारत में किया गया प्रमाणन अब वॉशिंगटन में नतीजा ला सकता है। अगर आपका कारोबार certificate of origin, निरीक्षण रिपोर्ट, गुणवत्ता प्रमाणन या शिपिंग दस्तावेज़ जारी करता है, उन पर दस्तख़त करता है या उन पर निर्भर है — और ज़्यादातर निर्यातक इनमें से कम से कम एक को छूते हैं — तो कसौटी यह रखिए कि हर दस्तावेज़ वही कहे जो सच है और उस तक पहुँचा जा सके जिसने जाँचा। “एजेंट देख लेता है” अब जवाब नहीं रहा।

ख़ुद समझौते पर दस्तख़त कुछ पर नहीं हुए, और यह अख़बार अब भी tariff की कोई दर नहीं छापता। फ़रवरी के framework ने reciprocal दर **18%** रखी थी और व्हाइट हाउस के संयुक्त बयान में कपड़ा और रेडीमेड, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक, कार्बनिक रसायन, घर की सजावट और दस्तकारी उत्पाद उसमें गिनाए गए — यानी जयपुर जो भेजता है उसका ज़्यादातर। मगर framework फ़रवरी का था, उसके बाद Supreme Court ने reciprocal tariffs गिरा दिए, executive orders ने कुछ उत्पादों पर 10% लगाया, और एक ही स्रोत ने Section 122 के तहत सार्वभौमिक 15% बताया। पाँच आँकड़े, आठ महीने, कोई दस्तख़त नहीं। clause अब भी आँकड़े से बेहतर है।

लागत · आने वाले आँकड़े

कल आने वाला महँगाई का आँकड़ा $113 पर नापा गया था। वह अभी से ग़लत है

अक्तूबर का CPI 12 नवंबर को · अक्तूबर का WPI 16 नवंबर को

अक्तूबर में इसी अख़बार ने यही कहा था, और और उल्टे चिह्न के साथ दोबारा कहना बनता है, क्योंकि इससे जो ग़लती बनती है वही महँगी है। **अक्तूबर का CPI** कल, **12 नवंबर** को आएगा, और **अक्तूबर का WPI 16 नवंबर** को। दोनों अक्तूबर नापते हैं। अक्तूबर वह महीना था जब ब्रेंट $113 से $117 के बीच रहा। दोनों में **$91** वाला बैरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह नवंबर में हुआ। यानी इस हफ़्ते दो आँकड़े छपेंगे जो ऐसा लागत-माहौल बताएँगे जो अब है ही नहीं — और उन्हें ताज़ा आँकड़ा कहकर छापा जाएगा, जो वे हैं।

अक्तूबर में इस अख़बार ने कहा था: आँकड़े का इंतज़ार किए बिना दाम बदलिए, क्योंकि आँकड़ा बाज़ार से पाँच हफ़्ते पीछे है। वह सही था और एक तरफ़ काटता था। इस महीने वह दूसरी तरफ़ काटता है, और हिदायत दोनों तरफ़ एक जैसी नहीं है। अक्तूबर का ऊँचा आँकड़ा अभी दाम बढ़ाने की वजह **नहीं** है — जो लागत वह नापता है वह गिर चुकी। और नवंबर का गिरता बैरल उन्हें घटाने की वजह भी **नहीं** है, क्योंकि वह बिना दस्तख़त वाले मसौदे पर टिका है। अगले पखवाड़े की ईमानदार स्थिति यह है कि किसी के पास ताज़ा सरकारी लागत आँकड़ा है ही नहीं, और जो कोई एक बोल रहा है वह अक्तूबर बोल रहा है।

इस पखवाड़े का एक आँकड़ा ताज़ा है और लागत की बात में बनता है, क्योंकि वह उस सवाल को तय करता है जो इस अख़बार ने अक्तूबर में उठाया था और तब साबित नहीं कर पाया था। वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत का कच्चे तेल का **आयात बिल 46.3% बढ़ा**, जबकि **आयात की मात्रा वही रही**। यही दावा अंक 12 ने GST संग्रह से किया था — कि आयात पर टैक्स का 42% उछाल क़ीमत थी, विकास नहीं — और वह बिलकुल दूसरी तरफ़ से पक्का हो गया। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरत का **88.7%** आयात से पूरा करता है, इसलिए हिसाब अब उसी रफ़्तार से उल्टा चलेगा जिस रफ़्तार से सीधा चला था।

आपको क्या करना है

अपनी पिछली तीन निर्यात खेपें निकालिए और देखिए कि फ़ाइल के हर प्रमाणपत्र पर दस्तख़त किसने किए, और क्या उस व्यक्ति ने सचमुच वह जाँचा जिसका प्रमाण दिया। जहाँ दस्तावेज़ किसी और के कहने पर दस्तख़त हुआ हो, वहाँ तरीक़ा सवाल उठने के बाद नहीं, अभी ठीक कीजिए। हर फ़ाइल पर यह दस मिनट की जाँच है और इस महीने उपलब्ध सबसे सस्ता अनुपालन काम। दाम पर कुछ नहीं बदलता: **शिपमेंट की तारीख़ पर लागू duty** के हिसाब से quote कीजिए और contract में लिखिए — वही हिदायत जो अब पाँच tariff आँकड़ों और मुद्रा के पूरे चक्कर से ज़्यादा जी चुकी है।

आपको क्या करना है

कल के आँकड़े पर अपनी price list में कुछ मत कीजिए, और आज के बैरल पर भी कुछ नहीं। इस हफ़्ते करने लायक़ एक हिसाब है जो आपके लिए कोई नहीं छापेगा: जो तीन-चार inputs आपकी लागत का बड़ा हिस्सा हैं, उनका *आज* का भाव निकालिए — जैसे अक्तूबर में निकाला था — और प्रतिशत अक्तूबर वाले आँकड़े के बग़ल में लिख दीजिए। दो कॉलम की वह शीट ही दिसंबर तक आपके पास मौजूद अकेला ताज़ा लागत आँकड़ा है — और जिस पखवाड़े सरकारी आँकड़े बीत चुके महीने का हाल बताएँ, उस पखवाड़े वह दोनों से ज़्यादा क़ीमती है।

बाज़ार

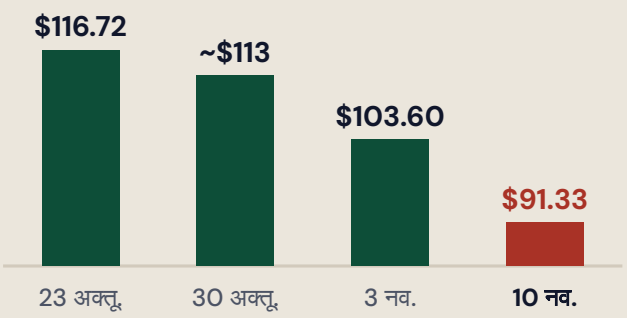
6 नवंबर 2026 तक का हफ़्ता · और दिवाली का सत्र

सूचकांक	बंद भाव	हफ़्ता
Nifty 50	25,030.35	+8.6%
Sensex	81,028.02	+8.8%

इस अख़बार का छापा सबसे बड़ा हफ़्ता। निफ्टी **1,977.25 अंक, 8.58%** चढ़कर **25,030.35** पर — लगातार सात सत्र की जीत, चौदह महीने की सबसे लंबी — और सेंसेक्स **8.82%** चढ़कर **81,028.02** पर, छब्बीस महीने की सबसे लंबी दौड़। हफ़्तों की बिकवाली के बाद **विदेशी संस्थाओं ने शुद्ध ₹45,960 करोड़ ख़रीदे**। यह कच्चे तेल ने किया: तरीक़ा पहले पन्ने पर है। दो सावधानियाँ। FII का आँकड़ा 6 नवंबर तक के हफ़्ते के लिए ₹45,960 करोड़ और "नवंबर के शुरुआती दिनों" के लिए ₹38,971 करोड़ बताया गया है — खिड़कियाँ अलग हैं, तथ्य अलग नहीं। और **8 नवंबर का मुहूर्त कारोबार** 402 अंक ऊपर खुला और *नीचे बंद हुआ*: सेंसेक्स **80,999.40** (-28.62), निफ्टी **24,986.40** (-43.95)। जिन रिपोर्टों ने शुरुआती बढ़त को नतीजा बताया वे दिन के बीच का आँकड़ा बोल रही थीं। हमने यह मोड़ नहीं पकड़ा और उसका दावा भी नहीं कर रहे।

ब्रेंट कच्चा तेल, डॉलर प्रति बैरल

23 अक्तूबर से 10 नवंबर 2026



पैमाना $85 से शुरू होता है, ज़ीरो से नहीं, ताकि 22% की गिरावट गिरावट जैसी दिखे। 30 अक्तूबर का भाव बाज़ार ने "करीब $113" बताया था — उसे अंदाज़े के तौर पर ही खींचा और लिखा गया है।

यही चार भाव हैं जिन पर पहला पन्ना अपनी बात रखता है। गिरावट सच है, और उसके नीचे की ज़मीन भी: ब्रेंट अब भी **साल भर पहले से 40.7% ऊपर** है, और 11 नवंबर को जहाज़ों पर हमले फिर शुरू होने पर यह दोबारा चढ़ा। चार्ट पंद्रह दिन का देखें, दाम साल भर का लगाएँ।

राजस्थान · RIICO

जिस खिड़की को हमने बंद बताया था वह बढ़ा दी गई। अब 20 नवंबर को बंद होगी

जोधपुर–पाली–मारवाड़ · 30 भूखंड · 30 अक्तूबर को 31 अक्तूबर से बढ़ाई गई

पिछले अंक में हमसे यह ग़लत हुआ, और और यही सुधार ही ख़बर है। अंक 12 ने आपसे कहा था कि **जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र** के आवेदन **31 अक्तूबर** को बंद हो गए। नहीं हुए। RIICO ने एक दिन पहले, **30 अक्तूबर** को बढ़ाने की सूचना लगाई, और खिड़की अब **20 नवंबर** तक चलती है — आज से नौ दिन। पेशकश है **30 भूखंडों** का direct allotment: **28 औद्योगिक** और दो मोटल या रेस्तराँ के लिए। पिछला अंक पढ़कर अगर आपने मान लिया था कि मौक़ा निकल गया, तो नहीं निकला।

यह ग़लती ठीक इसलिए नाम लेकर बतानी चाहिए कि वह वही सबक़ दोहराती है जो यह कॉलम तीन महीने से निकाल रहा है। तारीख़ किसी ऐसे ऐलान से नहीं खिसकी जो किसी तक पहुँचा हो; वह RIICO की अपनी साइट पर लगी सूचना से खिसकी, जिसे यह अख़बार सिर्फ़ देखने से मिला। इस कॉलम ने जितनी खिड़कियाँ बताईं — 12 अक्तूबर को बंद होता चरण 14, 13 और 14 को e-auction का EMD, और यह वाली — हर एक ठीक एक ही जगह मिलती थी, और कहीं नहीं। नतीजा वही है और अब उसके साथ एक सुधार भी जुड़ा है: portal ख़ुद देखिए, क्योंकि उसके बारे में पढ़ना — इस अख़बार में भी — धीमा है।

आवेदन से पहले एक चालू आदेश जानने लायक़ है, क्योंकि वह बदल देता है कि यह योजना किस आकार की यूनिट की पहुँच में है। RIICO के **1 सितम्बर 2026** के आदेश में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों के earmarked भूखंडों के लिए **लचीला भुगतान मॉडल — दस साल की क़िस्त सुविधा** — दी गई है। अंक 11 ने बताया था कि direct allotment योजना में प्रति भूखंड क़रीब ₹9.9 करोड़ का निवेश वादा बैठता है, और नतीजा निकाला था कि उससे काफ़ी छोटे project को पूछना चाहिए कि कौन सी श्रेणी उस पर बैठती है। दस साल की क़िस्त वाला विकल्प ठीक उसी समस्या का जवाब है — और क्षेत्रीय कार्यालय से पहला सवाल यही बनता है कि आपका क्षेत्र उन निर्दिष्ट क्षेत्रों में है या नहीं।

आपको क्या करना है

जोधपुर-पाली-मारवाड़ आपके काम का है तो आवेदन **20 नवंबर** को बंद होता है, और काग़ज़ी काम नौ दिन से ज़्यादा लेता है — आज ही शुरू कीजिए। क्षेत्रीय कार्यालय से एक ही फ़ोन में दो बातें पूछिए: 1 सितम्बर के आदेश में **दस साल की क़िस्त सुविधा** के लिए आपका क्षेत्र पात्र है या नहीं, और जो भूखंड आप चाहते हैं उन पर earnest money तथा allotment दर क्या है। और वह reminder लगा लीजिए जो यह कॉलम लगातार तीन अंक से माँग रहा है: हर महीने के पहले कामकाजी दिन riico.rajasthan.gov.in खोलकर सूचनाओं का पन्ना ख़ुद पढ़िए। यही अंक सबूत है — हमने आपके लिए पढ़ा और फिर भी तारीख़ तीन हफ़्ते ग़लत बताई।

स्टार्टअप की खबरें

2 – 6 नवंबर 2026 · Inc42 का हिसाब

- 2 से 6 नवंबर के बीच **20 स्टार्टअप** ने **$255 मिलियन** जुटाए, और सौदों की गिनती हफ़्ते भर में **38%** गिरी। कंपनियाँ कम, हर एक को कहीं ज़्यादा — ठीक पिछले पखवाड़े का उल्टा, जब 32 स्टार्टअप ने $130.2 मिलियन बाँटे थे। दो हफ़्ते, दो उलटी शक्लें, और इनमें से कोई रुझान नहीं है।
- **GIVA** क़रीब **$100 मिलियन** के साथ सबसे आगे — ज्वेलरी, और वैसा consumer-brand चेक जो पूरी तिमाही कम दिखा है। **Peppermint Robotics** ने फ़र्श साफ़ करने और सामान ढोने वाले स्वचालित रोबोट के लिए **$10.62 मिलियन** जुटाए — यह software की नहीं, पुणे की मैन्युफैक्चरिंग की कहानी है।
- हिसाब अब भी आपस में नहीं मिलते, और यह कॉलम अब भी अपने स्रोत का नाम लिखता है। ये आँकड़े 2–6 नवंबर के लिए **Inc42** के हैं। दूसरा tracker 2–7 नवंबर के लिए **22 सौदों में $290.55 मिलियन** बताता है — एक दिन ज़्यादा और तरीक़ा अलग, और यही ज़्यादातर फ़र्क़ है। हफ़्तों की तुलना एक ही tracker के भीतर कीजिए; दो के आर-पार कभी नहीं।

संदर्भ · आने वाले हफ़्ते

return में दस दिन, और जो महीना ब्याज तय करेगा उसमें उन्नीस

11 नवंबर से 4 दिसंबर 2026

आज filing का दिन है, और और उसके बाद महीना कैलेंडर से ज़्यादा तंग है। **11 नवंबर** — आज — मासिक भरने वालों के लिए अक्तूबर की **GSTR-1** है। फिर **12 नवंबर** को अक्तूबर का CPI और **16 नवंबर** को अक्तूबर का WPI — दोनों deadline नहीं, और दोनों लागत वाले कॉलम में। **15 नवंबर** को Q2 के TDS certificates Form 16A में। **20 नवंबर** को अक्तूबर की GSTR-3B। **21 नवंबर** को ऑडिट वालों की ITR। **30 नवंबर** को जहाँ section 92E लागू है वहाँ की ITR — और जिनका self-assessment tax अब भी बक़ाया है, उनके लिए सस्ते ब्याज वाले महीने का आख़िरी दिन भी।

फिर महीना उस एक तारीख़ पर ख़त्म होता है जो deadline नहीं है और अगली तिमाही का रुख तय करेगी। **MPC 2–4 दिसंबर** को बैठेगी। महीना भर पहले कुछ अर्थशास्त्री बड़े क़दम की दलील दे रहे थे; कच्चा तेल क़रीब पाँचवाँ हिस्सा गिरने के बाद पाठ पलटकर यह हो गया है कि बैंक के पास रुकने की गुंजाइश है। यह अख़बार इसका अनुमान नहीं लगा रहा। काम की बात यह है कि दिसंबर में रुकना, अगर आए, तो अक्तूबर के उन महँगाई आँकड़ों के तीन हफ़्ते बाद आएगा जो ऊँचे दिखेंगे — इसलिए कल के CPI को यह बताने वाला मत मानिए कि MPC क्या करेगी।

एक ग़ैर-क़ानूनी तारीख़ दर्ज करने लायक़ है क्योंकि वह बीत चुकी है और पाठकों ने सुर्ख़ियाँ देखी होंगी। **मुहूर्त कारोबार रविवार 8 नवंबर** को हुआ, और संवत 2083 उनहत्तर साल में पहली बार दोपहर के सत्र में खुला। सेंसेक्स क़रीब **402 अंक** ऊपर खुला और फिर लौटा दिया: वह **80,999.40** पर बंद हुआ, 28.62 अंक नीचे, और निफ्टी **24,986.40** पर, 43.95 नीचे। कुछ रिपोर्टों ने शुरुआती बढ़त को ही नतीजा बताकर छापा। सत्र मामूली गिरावट पर ख़त्म हुआ।

इस हफ़्ते का सवाल

हर अंक में एक

“तेल गिर गया है और रुपया मज़बूत है। मेरा ग्राहक अभी से दाम घटाने को कह रहा है। उसे क्या कहूँ?”

उसे सच बताइए — और वह सुनने में जितना लगता है उससे बेहतर सौदेबाज़ी की जगह है। ब्रेंट 23 अक्तूबर के **$116.72** से 10 नवंबर को **$91.33** पर आया — क़रीब पाँचवाँ हिस्सा — और वह भी अमेरिका–ईरान जंग ख़त्म करने के एक **मसौदे** पर, जिस पर दस्तख़त नहीं हुए, जिसकी शर्तें छपी नहीं, और जिसके दौरान होर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले चलते रहे और **11 नवंबर** को फिर हुए। ब्रेंट अब भी साल भर पहले से **40.7% ऊपर** है। बिना दस्तख़त वाले काग़ज़ पर बना भाव बातचीत टूटते ही पलट सकता है, और तब घटा हुआ दाम आपके हाथ में रह जाएगा और लागत ऊपर। फिर बात को बचाव नहीं, ठोस बनाइए। एक: आपकी अपनी लागत पाँचवाँ हिस्सा नहीं गिरी है, और आप यह दिखा सकते हैं — भाड़ा और ईंधन से जुड़ी लाइनें तेज़ चलती हैं, मगर resin, packaging और मज़दूरी नहीं; आपने जो ख़रीदा उसमें ज़्यादातर अक्तूबर की लागत अब भी बैठी है। दो: कटौती की जगह तरीक़ा पेश कीजिए। ऐसा **price-revision clause** जो तय दायरे से बाहर दोनों तरफ़ दाम हिलाए, उसे गिरावट तब देगा जब वह असली और टिकाऊ हो, और पलटने पर आपको बचाएगा — यह सीधे मना करने से बेहतर पेशकश है, और ऐसी कटौती से कहीं बेहतर जो वापस नहीं ली जा सकती। तीन: उसे अभी निश्चितता चाहिए तो उसी के लिए **तय अवधि वाला तय-दाम contract** होता है, और उसका दाम उस जोखिम के हिसाब से लगना चाहिए जो आप ले रहे हैं। न करने लायक़ एक ही काम है: सुर्ख़ी हिलने पर list price घटा देना। सुर्ख़ियाँ छह हफ़्ते में चार बार हिली हैं और आपकी price list को नहीं हिलना चाहिए था।

अपना सवाल भेजिए — हर अंक में एक का जवाब देते हैं

आपको क्या करना है

अगले दस दिन में तीन काम, इसी क्रम में। आज की **GSTR-1** भर दीजिए। इस हफ़्ते, 21 की ITR से पहले, अपने accountant से **234A और 234B का आँकड़ा रुपयों में** ले लीजिए, ताकि कब भरना है यह फ़ैसला आँकड़े से हो। और अगर कुछ 21 से आगे खिसकना ही है, तो पक्का कीजिए कि वह **30 नवंबर** से आगे न खिसके — महीने का हिस्सा पूरा महीना गिना जाता है, और 30 तथा 1 दिसंबर के बीच का फ़र्क़ दो अलग धाराओं पर पूरे एक महीने का ब्याज है।

इकॉनमी एक नज़र में

ब्रेंट कच्चा तेल		$91.33
10 साल की G-sec		~7.15%
रुपया	94.47/$	21 अक्तूबर के बाद सबसे मज़बूत
रेपो रेट	5.50%	MPC 2–4 दिसंबर; अब रुकने का पाठ
कच्चे तेल का आयात बिल		+46.3%
आयात पर निर्भरता		88.7%

Trading Economics और World Oil Monitor (ब्रेंट), Business Standard तथा Swarajya (यील्ड, रुपया), RBI (नीति), WION (आयात निर्भरता और छमाही का बिल)। इस हफ़्ते 10 साल की यील्ड श्रृंखला के हिसाब से 7.12% से 7.20% और ब्रेंट दिन के हिसाब से $91.33 से $92.53 बताया गया है — यह तालिका तारीख़ वाले आँकड़े रखती है और फ़ासले का नाम लेती है, ऐसी सटीकता का दावा नहीं करती जो किसी के पास नहीं है।

हमने क्या कहा, और हुआ क्या

पिछला अंक, रिकॉर्ड से मिलाकर

ग़लत निकला **अंक 11 · बड़ी खबर**

> "RBI ने 25 अंक बढ़ाए। बाज़ार 28 और जोड़ चुका है" — 10 साल की यील्ड 7.474%, और भरोसेमंद कोई नहीं मानता कि यह इस तिमाही नीचे आएगी।

वह वापस क़रीब **7.15%** पर है — पूरी बढ़त तीन हफ़्ते में लौट गई, क्योंकि कच्चा तेल पाँचवाँ हिस्सा गिरा। हमने जो तरीक़ा बताया था (MCLR बॉन्ड बाज़ार के पीछे, EBLR रेपो के पीछे) वह सही था और है। मगर 'भरोसेमंद कोई नहीं मानता' वाला वाक्य रिपोर्टिंग के भेस में अनुमान था, और यह अख़बार उसे न लिखता तो बेहतर था।

ग़लत निकला **अंक 12 · राजस्थान**

> "जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के आवेदन 31 अक्तूबर को बंद हो गए।"

नहीं हुए। RIICO ने **30 अक्तूबर** को बढ़ाने की सूचना लगाई और खिड़की **20 नवंबर** तक है। जिस पाठक ने हम पर भरोसा किया उसने 30 औद्योगिक भूखंडों पर तीन हफ़्ते गँवाए। सुधार इसी अंक का राजस्थान कॉलम है।

सही निकला **अंक 10–12 · लागत**

> "हर quotation में ईंधन का clause डालिए — दाम quotation की तारीख़ की ईंधन लागत मानकर, और तय दायरे से बाहर किसी भी तरफ़ हिलने पर फिर खुलेगा।"

ब्रेंट छह हफ़्ते में $102.70 से $116.72 और वापस **$91.33** पर गया। किसी भी सिरे पर तय किया गया दाम अब ग़लत है। यह अख़बार जो अकेली हिदायत दोनों दिशाओं में परखी गई और दोनों में टिकी, वह यही clause है।

सही निकला **अंक 12 · बड़ी खबर**

> "आयात पर टैक्स का 42% उछाल अपने आप में तेज़ अर्थव्यवस्था का सबूत नहीं है... देश वही चीज़ें महँगी क़ीमत पर ख़रीद रहा है।"

इस पखवाड़े दूसरी तरफ़ से पुष्टि: साल की पहली छमाही में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल **46.3%** बढ़ा, जबकि **मात्रा वही रही**। क़ीमत, विकास नहीं — और अब वही हिसाब उसी रफ़्तार से उल्टा चल रहा है।

हर अंक में छपता है। पिछला रिकॉर्ड archive में है। अगर कोई बात इस खाने से छूट गई है जो आपको लगती है कि तुलनी चाहिए, लिख भेजिए — अगले हफ़्ते तुलेगी, उनमें वे भी जो हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं।

इनमें से कोई खबर आप पर लागू होती है ?

बस एक मैसेज कीजिए। हम बता देंगे कि आप पर क्या लागू होता है, कब तक करना है, और किस बात की चिंता नहीं करनी। फिक्स्ड मंथली फीस, कोई लॉक-इन नहीं, नोटिस आया तो वो भी हम देखेंगे — जैसे 1,100+ MSME के साथ पहले से कर रहे हैं।

लोग हमारे पास क्यों आते हैं

- फिक्स्ड मंथली फीस — न छुपा चार्ज, न लॉक-इन
- सब कुछ WhatsApp पर। नोटिस आया तो वो भी हम देखेंगे।
- 7 दिन में books बंद, हर महीने P&L डैशबोर्ड

किसी कारोबारी के काम की है? आगे भेज दीजिए।

The Consulting Crew

theconsultingcrew.in
hello@theconsultingcrew.in
WhatsApp +919251022710
जयपुर · पूरे भारत में

हम क्या करते हैं

GST · इनकम टैक्स · TDS · ROC · पेरोल · CFO सलाह · कंपनी और LLP रजिस्ट्रेशन

अगला अंक

रविवार, 15 नवंबर 2026

पिछले अंक

हर अंक, मुफ़्त

THECONSULTINGCREW.IN

खबरें कहाँ से

कच्चा तेल — बिना दस्तख़त वाले मसौदे पर बैरल से पाँचवाँ हिस्सा — 24/7 Wall St — oil at its lowest since August as Trump calls the war 'effectively over', OilPrice — prices plunge as a draft proposal to end the US–Iran war circulates, Trading Economics — Brent at $91.68 on 10 November, -14% on the month, Global Oil Shock — week 45: Brent falls 8% · ब्याज दर और रुपया — पूरा चक्कर — Business Standard — rupee at a one-month high, 10-year yield down to 7.17%, Swarajya — yields slide to 7.15% as oil retreats, and what it means for December · बाज़ार — इस अख़बार का छापा सबसे बड़ा हफ़्ता — Kotak Neo — FII inflows of ₹45,960 crore as the Nifty rallies 8.6%, HDFC Sky — Sensex up 1,718 points, Nifty reclaims 25,000, BlinkMoney — the week, and the competing FII window, Kotak Neo — Muhurat trading closed lower in the first session of Samvat 2083 · GST — चौंतीस दिन, और अब भी कोई अधिसूचना नहीं — Trilegal — key recommendations of the 57th GST Council meeting, TaxGuru — arrest powers, ITC, refund and registration reforms, KarSathi — why section 69's removal needs Parliament first · व्यापार — प्रमाणन पर प्रतिबंध, और अब भी कोई दस्तख़त नहीं — US News / Reuters — Goyal says the deal will not hurt farmers, White House — the February joint statement and the 18% framework, India Briefing — the interim agreement, and what it covers · राजस्थान — जिस खिड़की को हमने बंद बताया — RIICO — the notices page, where the extension was posted on 30 October, RIICO — the orders page, including the 1 September instalment facility · स्टार्टअप — और जिस tracker को यह कॉलम बोल रहा है — Inc42 — $255 mn across 20 startups, 2–6 November, Best Startup India — the competing $290.55 mn across 22 deals, 2–7 November

ज़रूरी सूचना। यह अख़बार The Consulting Crew अपने क्लाइंट और जान-पहचान वालों की जानकारी के लिए निकालता है। यह कोई कानूनी, टैक्स या निवेश की सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से हमारा-आपका क्लाइंट रिश्ता नहीं बनता। आँकड़े, दरें और तारीख़ें छपने के दिन तक की हैं और सरकार के नोटिफिकेशन से बदल सकती हैं। कुछ भी करने से पहले अपने केस के हिसाब से हमसे एक बार पूछ लीजिए। बाज़ार के आँकड़े सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं, कोई शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं।